Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-12, Issue-2, September-2018

राष्ट्रीय आदोंलनों में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों एवं कृषकों का योगदान

डॉ० सीमा द्विवेदी
शोधार्थी इतिहास अध्ययन शाला प० रविंशकर विश्वविधालय,रायपुर(छ०ग०)

सारांश –1920 से भारतीय राष्ट्रीय आंन्दोंलन के इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। इस समय से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक भारतीय राजनीति और भारतीय राष्ट्रीय आंन्दोंलन गाँधी जी से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों और सूझ–बूझ से राष्ट्रीय आंन्दोंलन की प्रकृति को ही बदल दिया। गाँधी जी से पहले कांग्रेस केवल पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की संस्था थी। उसका आम जनता से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। गाँधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस को भारत की निर्धन जनता से सर्म्पक कराया। वे बार बार इस बात पर बल देते रहे कि वास्तविक भारत गाँवों में बसता है। भू–राजस्व व्यवस्था प्राचीनकाल से ब्रिटिशकाल तक निरंतर चलती रही,किन्तु भारतीय किसान ब्रिटिशकाल में ही इस भू–राजस्व व्यवस्था से अधिक व्यथित एवं पीड़ित हुआ,जिसके फलस्वरूप वह शोषण के विरूद्ध लड़ाई के लिए तत्पर हुआ। यद्यपि ब्रिटिशकाल से पूर्व एवं मुगलकाल के अतिंम समय में कुछ स्थानों पर किसान विद्रोहों का उल्लेख मिलता हैं। ऐसे किसान विद्रोहों की व्यापकता क्षेत्रीय थी। ब्रिटिश काल में साम्राज्यवादियों ने जमींदारों पर कृषकों से अधिक कर दोहन करने का बोझ डाल दिया था। अतः वे किसानों का अत्यधिक शोषण करने लगे। भारतीय कृषक को यह आभास होने लगा था कि ब्रिटिश शासक व कर्मचारी उसके द्वारा दिये जाने वाले धन को विकास के कार्य में खर्च न करके अपने एशोआराम पर व्यय करते हैं और कर की राशि का बड़ा भाग ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त साम्राज्यवादियों ने भारत के कुछ क्षेत्रों बंगाल,बिहार आदि स्थानों पर वहाँ के किसानों को ऐसी फसलें उपजानें के लिए विवश किया, जिसका फायदा किसानों को कम ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक होता था। इन कारणों से ब्रिटिश काल में भारतीय किसान आंदोलन करने के लिए विवश हुए। इसकाल में किसान आंदोंलन की शुरूआत 1772 के सन्यांसी किसान विद्रोह के रूप में हो गया था। इनमें भी भूमि बन्दोंबस्त कानून के विरोध में आदिवासियों का किसान विद्रोह,जो कि छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में हिसांत्मक हुआ था, इसका उल्लेख मिलता हैं। जिसे ब्रिटिश सरकार ने दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कुचल दिया था। 18वीं सदीं की तुलना में 19वीं सदीं के किसान आदोंलन के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी मिलती है, जिसमें बंगाल का नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, फड़के विद्रोह, बिहार का मुंड़ा आदिवासियों के विद्रोह प्रमुख है। ये ब्रिटिश सरकार को अधिक नुकसान नहीं पहुँचा सके, किन्तु जहाँ–जहाँ भी इन विद्रोहों को कुशल नेतृत्व मिला एवं संगठित शक्ति के रूप में लड़े गये, वहाँ–वहाँ इन्हें सफलता अवश्य मिली। इन विद्रोहों में सार्वभौमिकता एवं सर्वव्यापकता का अभाव रहा,जिससे किसानों को कोई बड़ीं उपलब्धि हासिल नहीं हो सकीं। 19वीं सदीं के किसान आन्दोंलन की तुलना में 20वीं सदीं के किसान आन्दोंलन अधिक संगठित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इसका श्रेय गाँधीं जी व राजनैतिक संगठनों को जाता हैं। आदिवासी किसान और किसान आंन्दोंलन के दो पहलू थे। दोनो का आजादी के संघर्ष से संबध था। एक पहलू था, किसानों और आदिवासी का आजादी के संघर्ष में शामिल होना। इसने संघर्ष को जन–आधार प्रदान किया और इसे वास्तविक जन–आदोंलन बना दिया। दूसरा पहलु, किसानों की शिकायतों से संबधित था।

कुँजी शब्द :– सार्वभौमिकता ,सर्वव्यापकता ,दण्डात्मक, भू–राजस्व, जन–आदोंलन ।

भारत के इतिहास में एक महान् घटना 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है। जिसने भारतीयों में एक नवीन आत्म जागृति की भावना विकसित की पुर्नजागरण के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति की गतिहीनता समाप्त हुई। भारतीयों में अपने गौरवपूर्ण अतीत के प्रति पुनः सम्मान की भावना पैदा हुई। इस पुनर्जागरण के अंतर्गत अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहनराय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद आदि ने 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, पुर्नजागरण के माध्यम से राजनीतिक चेतना का विकास किया। राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में यह एक उल्लेखनीय प्रयास था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ मध्यप्रांत में व्यापक पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप गाँधी युग के प्रारंभ से पूर्व कांग्रेस के शिक्षित तथा प्रमुख वर्ग तक सीमित था। 19वीं सदी के किसान विद्रोह का स्वरूप प्रायः स्थानीय स्तर पर ही किए गए किसी राजनीतिक दल या आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था। 20वीं सदी के किसानों का असंतोष की स्वाधीनता संघर्ष ने नियमित संवैधानिक और शांतिपूर्ण आंदोलन में बदल दिया।

महात्मा गाँधी के राजनीतिक उत्कर्ष के साथ ही सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उस समय की सर्वाधिक जागरूक धमतरी तहसील थी। कण्डेल सत्याग्रह के कारण गांधी जी का धमतरी आगमन हुआ। कांग्रेस ने सन् 1919 में कलकत्ता अधिवेशन में और 1920 में नागपुर अधिवेशन में गाँधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर समर्थन दिया। गाँधी जी ने अंग्रेस सरकार के समक्ष तीन माँग रखी –

1. अंग्रेज सरकार अमृतसर हत्याकाँड के लिए खेद प्रकट करें।
2. टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करें।
3. कोई नहीं संवैधानिक सुधार की योजना प्रस्तुत करें।

जब अंग्रेज सरकार ने इन माँगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तब गाँधी जी ने अगस्त सन् 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया इस आंदोलन के दो स्वरूप थे –

1. रचनात्मक 2. विंध्वसात्मक।

रचनात्मक कार्यो में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन, तिलक कोष में एक करोड़ जमा करना, अनेकानेक स्वयं सेवकों की भर्ती करना और 20 लाख चरखों को बेरोजगारों में वितरित करवाना। आंदोलन के विध्वंसात्मक स्वरूप में विदेशी वस्तुओं , अंग्रेज न्यायालयों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। गाँधी जी का यह संपूर्ण असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। 1920–21 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और सारे देश में फैल गया।

इस समय छत्तीसगढ़ में भी यह आंदोलन तीव्र हो उठा। धमतरी भी इससे अछूती नहीं रहीं इस नगर के लोग नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में एक नवीन चेतना लेकर वापस लौटे यहां इस आंदोलन का श्री गणेश कण्डेल नहर सत्याग्रह से हुआ।[1] धमतरी का राष्ट्रीय आंदोलन योगदान रहा। इस आंदोलन में पं. सुन्दरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का योगदान अविस्मरणीय रहा। महानदी पर रूद्री और माडमसिल्ली पर बाँध बनाये गये थे। इससे ब्रिटिश शासन ने नहर निकाली थी इससे गाँवो में सिंचाई की जाती थी। शासन इस पर 'नहर कर' वसूल करता था। इस कर को अदा करने के लिए गाँवों को दस वर्षीय अनुबंध करना होता था। यह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि ग्रामवासी इस राशि से अपने गाँव में हमेशा के लिए सिंचाई का एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतएव बहुत कम गाँवों इस अनुबंध हेतु तैयार हुआ।[2]

नहर क्षेत्र में कण्डेल ग्राम भी आता था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसी गांव के रहने वाले थे। वे इस समय तक देशभक्त के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। नहर विभाग का कार्य संतोषप्रद नहीं था क्योंकि अनुबंध अधिक नहीं हो रहे थे विभाग ने अगस्त में 1920 में तय किया और एक षडयंत्र रचा कि एक नाली बनाकर पानी कण्डेल में बहा दिया जाए। कि पूरे गाँव में सिंचाई हो

सके। इससे उन्हें दोहरा लाभ था। एक तो इस आधार पर शासन कण्डेल ग्राम में चोरी से पानी लेने के आरोप में हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध हेतु उन्हें बाध्य कर सकें। दूसरा, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव पर भी आरोप लगाकर उन्हें देश प्रेम से विरक्त किया जा सकें। किन्तु इस योजना के कार्यान्वयन के साथ उसी रात्रि कण्डेल एवं आसपास के क्षेत्रों में इतनी घनघोर वर्षा हुई। नहर अधिकारियों द्वारा नहर से पानी चोरी का आरोप लगाया गया तब ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। ग्रामवासियों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन किया किन्तु अंग्रेजों ने इसकी परवाह न करते हुए 4303 रू. की रकम जबरदस्ती वसूली करने हेतु कुर्की वांरट जारी कर दिया।[3] की सभा कण्डेल में हुई। जिसमें नेताओं को उन पर हो रहे अत्याचारों से अवगत कराया गया निर्णय लिया गया कि इससे असंतोष षढ़ गया और नेताओं की सभा कंण्डेल में हुई। इसका विरोध कांग्रेस द्वारा सुझाए गए सत्यागृह द्वारा किया जाएगा।[4] शासन ने दमन चक्र के तहत उसने गांव वालों के पशुओं को कुर्क कर लिया तथा नीलामी करके उक्त राशि प्राप्त करने की योजना बनाई तथा सर्वप्रथम इस ग्राम के पशुओं को इतवारी बाजार में नीलामी के लिए लाया गयी लेकिन कोई ने भी बोली लगाने के लिए सामने नहीं आया। शासन अब बुरी तरह से खिन्न हो चुकी थी।[5] रायपुर से डिप्टी कमिश्नर ने वस्तु स्थिति को संभालने हेतु आंदोलन स्थल पर भेजा गया। उन्होनें पहुंचकर जांच पड़ताल की जिससे उन्हें सच्चाई का पता चला लेकिन प्रशासन की त्रुटि को छुपाने के लिए लगान की राशि आाधा कर दिया फिर चौथाई करके गाम वासियों से वसूलने का प्रयास किया किन्तु किसान अडे रहने के कारण उन्हें संपूर्ण राशि माफ करने की शासकीय घोषणा करनी पड़ी।[6] इस प्रकार छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में रायपुर जिले का कण्डेल नहर सत्याग्रह विख्यात हुआ। नगर–सिहावा आदिवासी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह (धमतरी में जंगल सत्याग्रह) 1922 में हुआ। इस क्षेत्र के आदिवासी में जागृति पैदा हो गई थी। इस सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। श्री श्यामलाल जी सोम (नगरी) श्री पंचम सिंह जी (उमरगांव) श्री मुंडरा ठाकुर, श्री चाली ठाकुर तथा श्री विशंभर पटेल जी आदि की मंत्रणा से सर्वप्रथम वन विभाग के शासकीय लकड़ी के कूप से अपनी खेती के निस्तार तथा जलाने के लिए वनों से लकड़ी लाकर अपने सत्यागह को प्रारंभ किया। इसका कारण था कि वन विभाग के कर्मचारी इन आदिवासियों से बेगार अथवा अल्प मजदूरी में कार्य करने को विवश करते थे इस तरह आदिवासी शासन के इस अत्याचार के विरूद्ध हो गए।

यह जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 ई. के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ। स्वयं सेवकों ने सत्याग्रह करने की मौखिक सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी सत्याग्रह के तीसरे दिन अंग्रेज अधिकारी बेली सशस्त्र पुलिस बल के साथ सत्याग्रहियों एवं जनता को आंतकित करने नगरी पहुंचे। यहाँ पहुंच कर इन्होने बर्बरता का ताण्डव नृत्य शुरू किया। इन्होनें सत्याग्रहियों एवं आम जनता के घरों की तलाशी ली। जिसमें लोगों की निजी लकड़ियों को भी घर से बाहर निकाला गया। उन पर चोरी का आरोप लगाकर गॉव में ही अदालती कार्यवाही करके फौजी अदालत के समान निर्णय दिये जाने लगे।[7]

इस तरह सिहावा नगरी का यह जंगल सत्याग्रह अत्याधिक कठिनाइयों तथा यंत्रणाओं और आर्थिक क्षति के साथ सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। असहयोग आन्दोंल के समान ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी छत्तीसगढ़ के किसान आदिवासियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें गट्टासिल्ली एवं रूदी नवागांव के जंगल सत्याग्रह प्रमुख है। धमतरी के सिहावा परगना के ठेमली नामक गांव के करीब तीन सौ मवेशियों को वन विभाग के अधिकारियों ने आरक्षित क्षेत्र की घास चरने के अपराध में गट्टासिली गांव के कांजी हाऊस में बंद कर दिया। इस घटना की जानकारी कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों नारायण राम मेघावाले, नत्थूजी जगताप एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के पास तक पहुॅचा। इन्होने ग्रामवासियों की सहायता का पूरा आश्वासन दिया।[8]

सत्याग्रहियों ने देखा कि पशुओं को कांजी हाऊस से निकालकर नीलाम करने हेतु बाजार ले जाने की तैयारी हो रही थी। गांव वालों के साथ मिलकर सत्याग्रहियों ने जानवरों को मुक्त करने का अनुरोध किया लेकिन उत्तर नकारात्मक मिला। तब स्वयं सेवकों ने अहिंसाक सत्याग्रह का सहारा लिया। मेवेशियों को निःशुल्क मुक्त कराने हेतु कांजी हाऊस के द्वारा के समक्ष वे लेट गए। ये सभी प्रशिक्षित सत्याग्रही थे अतः इन्होने पुलिस के सभी अत्याचारों को सहा। अतः शासकीय कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों से विचार विर्मश किया तथा अंत में सभी मवेशियों को निःशुल्क मुक्त कर दिया।

इस प्रकार छ.ग. में अन्य आन्दोंलन हुए जिसमें राजिम किसान सभा फरवरी–1920, हुई रियासतें में लगान बंदी आन्दोलन 1934, कांकेर में किसान आन्दोलन 1944–45, सक्ती रियासत में किसान आन्दोलन, बिलासपुर में जंगल सत्याग्रह एवं कृषक आन्दोलन इत्यादि। 1857 ई. के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों ने भी भाग लिया तथा अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया किन्तु इसके असफल होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अग्रेंजों ने अधिकारियों को अधिक अधिकार प्रदान की। महात्मा गाँधी ने 1921 ई. में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया। यह आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। तथा कृषकों ने भारी संख्या में इस आन्दोंलन में भाग लिया। किन्तु महात्मा गाँधी के द्वारा इस आंदोलन को अचानक समाप्त की जाने की वजह से यह आन्दोलन असफल ही रहा। इस आन्दोलन को इतना लाभ अवश्य हुआ कि उनमें आन्दोंलन करने के साहस में वृद्धि हुई व वे संगठित होने का प्रयत्न करने लगे। किसानों ने तब तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं किया था। किसानों ने न केवल समय–समय पर आर्थिक व अन्य कारणों से विद्रोह किए वरन राष्ट्रीय आन्दोलंन में भी भाग लेकर देश का स्वतंत्रत कराने का प्रयत्न किया।''

निष्कर्ष :–उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। कि भारतीय किसान व किसान आदिवासी ब्रिटिशकालीन भू–राजस्व व्यवस्था से अधिक व्यथित एवं पीड़ित थे, जिसके फलस्वरूप वह शोषण के विरूद्ध लड़ाई के लिए तत्पर हुए। यद्यपि ब्रिटिशकाल से पूर्व एवं मुगलकाल के अतिंम समय में कुछ स्थानों पर किसान विद्रोहों का उल्लेख मिलता हैं। ऐसे किसान विद्रोहों की व्यापकता क्षेत्रीय थी। 19वीं सदीं के किसान आन्दोंलन की तुलना में 20वीं सदीं के किसान आन्दोंलन अधिक संगठित थे। इसका श्रेय गाँधीं जी व राजनैतिक संगठनों को जाता हैं। 19वीं सदी के किसान विद्रोह का स्वरूप प्रायः स्थानीय स्तर पर ही किए गए किसी राजनीतिक दल या आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था। 20वीं सदी के किसानों के असंतोष को स्वाधीनता संघर्ष ने नियमित संवैधानिक और शांतिपूर्ण आंदोलन में बदल दिया। महात्मा गाँधी के राजनीतिक उत्कर्ष के साथ ही सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उस समय की सर्वाधिक जागरूक धमतरी तहसील थी।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. देवांगन–डॉ शोभाराम– ''धमतरी नगर और तहसील का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन'' अप्रकाशित पाण्डुलिपि–पृ.137, 1970 ।ट
2. वही – पृ.सं.–137–138
3. नगर पालिका परिषद् धमतरी द्वारा प्रकाशित ''शताब्दी वर्ष स्मारिका'' 26 जुलाई 1981, प्र.सं.–9
4. फाइल नं. आर सैकंड 5/3 फ्रीडय मूवमेंट इन धमतरी महासमुंद तहसील, पृ.सं. 1 नेशनल अफाईज नई दिल्ली।
5. मध्यप्रदेश/वर्ष 3/अंक 2/10 अगस्त 1977 प्र.सं. 5
6. वर्मा, शिंवसिंग– ''जी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव का राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन'' अप्रभावित पाण्डुलिपी पृ.सं.–5–6, 1983
7. रिपोर्ट आन द एडामिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल प्रविसेस एण्डबराट, 1921–22, खण्डि–1, प्र.सं.–321
8. शर्मा डॉ. अरविन्द – ''छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास'' पृ.सं. 169, सन् 1999